

Daily Current Affairs

29 June 2025

All Government

**ONE DAY
EXAMS!**



BANK



RAILWAY



SSC



TEACHING



STATE
EXAMS



Expert Live
Classes



Comprehensive
Study Material



Mock Tests &
PYQs



Performance
Tracking



25,000+ PDF
Study Material


Adda247
INDIA'S NO.1 GOVT JOB PREP APP



25,000+

FREE PYP PDFs

OR ATTEMPT AS



MOCK TESTS

START PRACTICING NOW! →

Daily Current Affairs Quiz 29 June 2026

Q1. UNCTAD की मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट 2025 की समीक्षा के अनुसार, कौन सा देश 2025 में दुनिया का अग्रणी जहाज पुनर्चक्रण (शिप रीसाइक्लिंग) राष्ट्र बन गया?

- (a) बांग्लादेश
- (b) पाकिस्तान
- (c) भारत
- (d) चीन

Ans.(c)

Sol. उत्तर: (c) भारत

व्याख्या

- संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन की रिपोर्ट "मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट 2025 की समीक्षा" के अनुसार, भारत 2025 में दुनिया का अग्रणी जहाज पुनर्चक्रण राष्ट्र बन गया।
- जहाज पुनर्चक्रण में भारत की वैश्विक हिस्सेदारी 2024 में 30.1% से बढ़कर 2025 में 35.4% हो गई।
- जहाज पुनर्चक्रण की मात्रा 1.86 मिलियन सकल टन (GT) से बढ़कर 2.99 मिलियन GT हो गई, जो लगभग 60% वृद्धि दर्ज करती है।
- भारत ने अपना मैरीटाइम इंडिया विजन (MIV) 2030 लक्ष्य समय से पांच साल पहले हासिल कर लिया।

Information Booster:

- शिप-ब्रेकिंग क्रेडिट नोट स्कीम (SbCN) स्क्रैप मूल्य का 40% के बराबर क्रेडिट प्रदान करती है, जिसे एक नए जहाज की लागत का 5% तक उपयोग किया जा सकता है।
- सरकार ने जहाज पुनर्चक्रण सुविधाओं के आधुनिकीकरण के लिए Rs.53.5 करोड़ भी प्रदान किए हैं।
- कुल 115 जहाज पुनर्चक्रण सुविधाओं को हांगकांग अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन (HKC) के अनुरूप बनाया गया है।
- यह पहल पर्यावरण के अनुकूल और सुरक्षित जहाज पुनर्चक्रण प्रथाओं का समर्थन करती है।

Additional Knowledge:

- अलंग-सोसिया जहाज पुनर्चक्रण यार्ड भारत की 97% जहाज पुनर्चक्रण गतिविधि को संभालता है।
- गुजरात मास्टर प्लान के तहत, इसकी क्षमता को 9 मिलियन लाइट डिस्प्लेसमेंट टन (LDT) तक बढ़ाया जा रहा है।
- अलंग-सोसिया को दुनिया का सबसे बड़ा जहाज पुनर्चक्रण केंद्र के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- सकल टन (GT) जहाज की कुल आंतरिक मात्रा का एक माप है, जबकि लाइट डिस्प्लेसमेंट टन (LDT) कार्गो, ईंधन, यात्रियों और स्टोर को छोड़कर जहाज के वजन को संदर्भित करता है।

Q2. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने परिवहन, गतिशीलता और रसद (लॉजिस्टिक्स) पर भारत का पहला स्थायी अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के लिए किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए?

- (a) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली (IIT दिल्ली)
- (b) नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (NCAER)
- (c) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी (NIPFP)
- (d) भारतीय सांख्यिकी संस्थान (ISI)

Ans.(b)

Sol. उत्तर: (b) नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (NCAER)

व्याख्या

- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने जून 2026 में नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- समझौता ज्ञापन का उद्देश्य परिवहन, गतिशीलता और रसद (लॉजिस्टिक्स) के अर्थशास्त्र के लिए समर्पित भारत का पहला स्थायी और स्वतंत्र अनुसंधान केंद्र स्थापित करना है।
- केंद्र नई दिल्ली में NCAER मुख्यालय में स्थापित किया जाएगा।
- इसका उद्देश्य सड़क परिवहन क्षेत्र में साक्ष्य-आधारित नीति-निर्माण और डेटा-संचालित निर्णय लेने को मजबूत करना है।

Information Booster:

- केंद्र निम्नलिखित पर अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान करेगा:
- परिवहन
- गतिशीलता
- रसद
- यह निम्नलिखित के लिए कार्रवाई योग्य अंतर्दृष्टि उत्पन्न करेगा:
- दीर्घकालिक योजना
- निवेश निर्णय
- नीति निर्माण
- अनुसंधान क्षेत्रों में शामिल हैं:
- राष्ट्रीय राजमार्ग अर्थशास्त्र
- माल रसद
- मॉडल एकीकरण
- टोल नीति
- परिसंपत्ति मुद्राकरण
- सड़क सुरक्षा हस्तक्षेप

Additional Knowledge:

- केंद्र का मार्गदर्शन एक सलाहकार समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें अर्थशास्त्री, परिवहन विशेषज्ञ, सार्वजनिक नीति विशेषज्ञ और शिक्षाविद शामिल होंगे।
- एन. आर. वी. वी. एम. के. राजेंद्र कुमार और सुरेश गोयल समिति के सदस्य होंगे।
- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत कार्य करता है।
- नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च भारत के प्रमुख स्वतंत्र आर्थिक नीति अनुसंधान संस्थानों में से एक है।

Q3. जून 2026 में भारत और इज़राइल के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (MoU) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. समझौता ज्ञापन भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और इज़राइल के सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान (SAI) के बीच हस्ताक्षरित किया गया था।
2. समझौते का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के ऑडिटिंग में सहयोग को मजबूत करना है।
3. समझौता ज्ञापन ऑडिटिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डेटा एनालिटिक्स और डिजिटल ऑडिट टूल्स के उपयोग को बढ़ावा देता है।
4. समझौता प्रदर्शन ऑडिटिंग और अनुपालन ऑडिटिंग को बढ़ाने पर भी केंद्रित है।

- (a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1, 3 और 4
(d) 1, 2, 3 और 4

Ans.(d)

Sol. उत्तर

(d) 1, 2, 3 और 4

व्याख्या

- कथन 1 सही है क्योंकि समझौता जापान भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और इजराइल के सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान (SAI) के बीच हस्ताक्षरित किया गया था।
- कथन 2 सही है क्योंकि समझौते का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के ऑडिटिंग में सहयोग को मजबूत करना है।
- कथन 3 सही है क्योंकि यह ऑडिट दक्षता और सटीकता में सुधार के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डेटा एनालिटिक्स और डिजिटल ऑडिट टूल्स के उपयोग पर जोर देता है।
- कथन 4 सही है क्योंकि समझौता जापान प्रदर्शन ऑडिटिंग और अनुपालन ऑडिटिंग को मजबूत करने पर भी केंद्रित है।

Information Booster

- समझौता जापान निम्नलिखित के बीच द्विपक्षीय बैठक के बाद हस्ताक्षरित किया गया:

- के. संजय मूर्ति
- मतान्याहू एंग्लमैन
- सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में शामिल हैं:
- AI-सक्षम ऑडिटिंग
- डेटा एनालिटिक्स
- डिजिटल ऑडिट टूल्स
- प्रदर्शन ऑडिटिंग
- अनुपालन ऑडिटिंग
- सार्वजनिक क्षेत्र की निगरानी में नवाचार
- शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही
- अपनी यात्रा के दौरान, मतान्याहू एंग्लमैन ने डॉ. बी.आर. अंबेडकर व्याख्यान श्रृंखला में सार्वजनिक क्षेत्र के ऑडिटिंग में AI की भूमिका पर व्याख्यान दिया।

Additional Knowledge

- भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत स्थापित एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकरण है।
- CAG केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) के खातों का ऑडिट करता है।
- सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान (SAI) किसी देश का सर्वोच्च सार्वजनिक ऑडिटिंग प्राधिकरण है।
- प्रदर्शन ऑडिट सरकारी कार्यक्रमों की अर्थव्यवस्था, दक्षता और प्रभावशीलता का मूल्यांकन करता है, जबकि अनुपालन ऑडिट यह जांचता है कि क्या सार्वजनिक प्राधिकरण लागू कानूनों, नियमों और विनियमों का अनुपालन करते हैं।

Q4. सैटशोर एनालिटिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने जून 2026 में जियोस्पेशियल इंटेलिजेंस (GEOINT) समाधानों पर सहयोग करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता जापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए?

- (a) एयरबस डिफेंस एंड स्पेस
- (b) थेल्स ग्रुप
- (c) सफरान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस
- (d) डसॉल्ट एविएशन

Ans.(c)

Sol. उत्तर: (c) सफरान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस

व्याख्या

- सफरान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस और सैटशोर एनालिटिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने जून 2026 में एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।
- सहयोग का उद्देश्य भारतीय बाजार के लिए जियोस्पेशियल इंटेलिजेंस (GEOINT) समाधान विकसित करना है।
- यह पहल फ्रांस-भारत नवाचार वर्ष का हिस्सा है, जो एयरोस्पेस और रक्षा प्रौद्योगिकियों में सहयोग को बढ़ावा दे रही है।
- साझेदारी बेहतर निर्णय लेने के लिए उपग्रह इमेजरी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), और खुफिया प्रणालियों को एकीकृत करेगी।

Information Booster:

- सहयोग निम्नलिखित को जोड़ता है:
- सफरान.AI की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षमताएं।
- सैटशोर की जियोस्पेशियल एनालिटिक्स और उपग्रह डेटा विशेषज्ञता।
- कालिडो स्पेस सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड एकीकृत पृथ्वी अवलोकन-से-खुफिया प्रणाली प्रदान करेगी।
- साझेदारी भारत के लिए एंड-टू-एंड GEOINT समाधान प्रदान करना है।

Additional Knowledge:

- समाधान निम्नलिखित का समर्थन करेंगे:
- रक्षा संचालन
- पर्यावरण निगरानी
- बुनियादी ढांचा सुरक्षा
- खुफिया और निगरानी
- GEOINT (जियोस्पेशियल इंटेलिजेंस) रणनीतिक और परिचालन निर्णय लेने का समर्थन करने के लिए इमेजरी, जियोस्पेशियल डेटा और विश्लेषण को जोड़ती है।
- यह सहयोग AI-सक्षम पृथ्वी अवलोकन और राष्ट्रीय सुरक्षा अनुप्रयोगों में भारत की क्षमताओं को मजबूत करने की उम्मीद है।
- फ्रांस-भारत नवाचार वर्ष उन्नत प्रौद्योगिकियों, अनुसंधान और नवाचार में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देता है।

Q5. जून 2026 में कितने चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के छात्रों को इंडियाAI फैलोशिप प्राप्त हुई?

- (a) 5
- (b) 6
- (c) 7
- (d) 8

Ans.(c)

Sol. उत्तर: (c) 7

व्याख्या

- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जून 2026 में चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के 7 छात्रों को इंडियाAI फैलोशिप प्रदान की।
- फैलोशिप नवीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग (ML) परियोजनाओं पर काम कर रहे इंजीनियरिंग छात्रों का समर्थन करती है।
- इंडियाAI फैलोशिप 2024 में इंडियाAI मिशन के फ्यूचर स्किल्स स्तंभ के तहत शुरू की गई थी।
- चयनित छात्र कंप्यूटर विज्ञान और संबंधित इंजीनियरिंग विषयों के हैं।

Information Booster:

- सात पुरस्कार विजेताओं में शामिल हैं:
- पांच B.Tech (AI & ML) छात्र
- एक B.Tech (कंप्यूटर विज्ञान और व्यावसायिक प्रणाली - CSBS) छात्र
- एक B.Tech (गेमिंग और ग्राफिक्स) छात्र
- प्रत्येक फैलोशिप प्राप्तकर्ता को अपनी अनुसंधान परियोजना का समर्थन करने के लिए Rs.1 लाख प्राप्त होते हैं।
- फैलोशिप उभरती AI प्रौद्योगिकियों में नवाचार को प्रोत्साहित करती है।

Additional Knowledge:

- चयनित परियोजनाएं निम्नलिखित क्षेत्रों पर केंद्रित हैं:
- शिक्षा प्रौद्योगिकी
- आपदा प्रतिक्रिया प्रणाली
- यातायात प्रबंधन
- डीप-लर्निंग-आधारित वास्तविक समय योग मुद्रा सुधार
- इंडियाAI मिशन अनुसंधान, नवाचार, कंप्यूटिंग बुनियादी ढांचे, डेटासेट, स्टार्टअप्स और भविष्य के लिए तैयार कौशल के माध्यम से भारत के AI पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है।
- फ्यूचर स्किल्स स्तंभ छात्रों और पेशेवरों के बीच AI प्रतिभा का निर्माण और उन्नत अनुसंधान का समर्थन करने पर केंद्रित है।

Q6. अंतरराष्ट्रीय विधवा दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है?

- (a) 21 जून
- (b) 22 जून
- (c) 23 जून
- (d) 24 जून

Ans.(c)

Sol. उत्तर: (c) 23 जून

व्याख्या

- अंतरराष्ट्रीय विधवा दिवस दुनिया भर में विधवाओं के अधिकारों और उनके सामने आने वाली सामाजिक, आर्थिक और मानवाधिकार चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 23 जून को मनाया जाता है।
- यह दिन भेदभाव, गरीबी, बहिष्कार, और विधवाओं के लिए कानूनी सुरक्षा की कमी जैसे मुद्दों पर प्रकाश डालता है।
- यह दुनिया भर में विधवाओं के लिए समानता, सम्मान और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपायों को बढ़ावा देता है।

Information Booster:

- यह दिन 2005 में लूंबा फाउंडेशन द्वारा शुरू किया गया था।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 दिसंबर 2010 को संकल्प A/RES/65/189 अपनाया, जिसमें 23 जून को अंतरराष्ट्रीय विधवा दिवस घोषित किया गया।
- पहला संयुक्त राष्ट्र-मान्यता प्राप्त पालन 23 जून 2011 को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय, न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था।

Additional Knowledge:

- 23 जून की तारीख को इसलिए चुना गया क्योंकि लॉर्ड राज लूंबा ने 23 जून 1954 को अपने पिता को खो दिया था, जब उनकी माँ एक विधवा हो गई थी।
- लूंबा फाउंडेशन वैश्विक स्तर पर विधवाओं और उनके बच्चों के कल्याण और अधिकारों में सुधार के लिए काम करता है।
- अंतरराष्ट्रीय विधवा दिवस सरकारों और संगठनों को विधवाओं के लिए कानूनी, वित्तीय, शैक्षिक और सामाजिक समर्थन को मजबूत करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

Q7. FY 2026-27 के लिए संशोधित केरल बजट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. संशोधित बजट वित्त मंत्री वी. डी. सतीशन द्वारा प्रस्तुत किया गया था।
2. बजट ने ₹400 करोड़ के आवंटन के साथ मिशन समुद्र की घोषणा की।
3. FY27 के लिए राजकोषीय घाटा (FD) GSDP का 3.46% अनुमानित है।
4. ओमन चांडी स्वास्थ्य बीमा योजना को ₹10 करोड़ का आवंटन प्राप्त हुआ।

- (a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1, 3 और 4
(d) 1, 2, 3 और 4

Ans.(d)

Sol. उत्तर

- (d) 1, 2, 3 और 4

व्याख्या

- कथन 1 सही है क्योंकि FY27 के लिए संशोधित बजट वी. डी. सतीशन द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिनके पास वित्त विभाग भी है।
- कथन 2 सही है क्योंकि मिशन समुद्र को ₹400 करोड़ का आवंटन प्राप्त हुआ।
- कथन 3 सही है क्योंकि राजकोषीय घाटा GSDP का 3.46% अनुमानित है।
- कथन 4 सही है क्योंकि ओमन चांडी स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए ₹10 करोड़ आवंटित किए गए थे।

Information Booster

- राजस्व प्राप्तियाँ: ₹1,69,646.37 करोड़
- राजस्व व्यय: ₹2,05,001.67 करोड़
- प्रमुख आवंटन:
 - मिशन समुद्र – ₹400 करोड़
 - एविएशन हब – ₹200 करोड़
 - इकोनॉमिक कॉरिडोर – ₹50 करोड़
 - मिनरल कॉरिडोर – ₹100 करोड़
 - लाइफ साइंस सिटी – ₹100 करोड़
 - ओमन चांडी स्वास्थ्य बीमा योजना – ₹10 करोड़

Additional Knowledge

- मिशन समुद्र तटीय रेखा, बंदरगाहों और अंतर्देशीय जलमार्गों को एकीकृत करने पर केंद्रित है।
- ओमन चांडी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रति परिवार ₹25 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करती है।
- राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और कुल प्राप्तियों (उधार को छोड़कर) के बीच के अंतर को दर्शाता है।

Q8. जून 2026 में बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय (MoPS&W) द्वारा किस बंदरगाह को स्कोप-2 उत्सर्जन मुक्त बंदरगाह के रूप में मान्यता दी गई थी?

- (a) जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह
(b) दीनदयाल बंदरगाह
(c) वी.ओ. चिदंबरनार बंदरगाह प्राधिकरण
(d) पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण

Ans.(c)

Sol. उत्तर: (c) वी.ओ. चिदंबरनार बंदरगाह प्राधिकरण

व्याख्या

- वी.ओ. चिदंबरनार बंदरगाह प्राधिकरण को जून 2026 में बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा स्कोप-2 उत्सर्जन मुक्त बंदरगाह के रूप में मान्यता दी गई थी।
- केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने घोषणा की कि बंदरगाह ने शुद्ध कार्बन उत्सर्जन में 45% की कमी हासिल कर ली है, जो इसे सतत समुद्री विकास के लिए एक मॉडल बनाता है।
- मान्यता स्वच्छ ऊर्जा और कम कार्बन वाले परिचालन की दिशा में बंदरगाह के परिवर्तन को मान्य करती है।
- इस आयोजन के दौरान शिक्षा, हरित ऊर्जा और डिजिटल परिवर्तन में छह नई पहलें भी समर्पित की गईं।

Information Booster:

- बंदरगाह ने अपनी पहली स्थिरता रिपोर्ट जारी की जिसका शीर्षक "VOCPA स्थिरता रिपोर्ट 2026: एक हरित समुद्री भविष्य की ओर" है।
- भारतीय प्रबंधन संस्थान कलकत्ता ने एक केस स्टडी जारी की जिसका शीर्षक "द हाइड्रोजन पिवट: ऑर्केस्ट्रेटिंग द ग्रीन ट्रांजिशन एट वी.ओ. चिदंबरनार पोर्ट अथॉरिटी" था।
- एक नए केंद्रीय विद्यालय ने 2026-27 सत्र के लिए शैक्षणिक गतिविधियों की शुरुआत की।
- पहलों की घोषणा ट्रांसपोर्ट भवन, नई दिल्ली में की गई थी।

Additional Knowledge:

- स्कोप-2 उत्सर्जन अप्रत्यक्ष ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को संदर्भित करते हैं जो खरीदी गई बिजली, भाप, हीटिंग या कूलिंग की खपत से उत्पन्न होते हैं।
- वी.ओ. चिदंबरनार बंदरगाह प्राधिकरण तूतीकोरिन, तमिलनाडु में स्थित है, और भारत के प्रमुख बंदरगाहों में से एक है।
- बंदरगाह का नाम वी. ओ. चिदंबरम पिल्लई के नाम पर रखा गया है, जिन्हें लोकप्रिय रूप से कप्पलोट्टिया तमिलन के नाम से जाना जाता है।
- हरित बंदरगाह उत्सर्जन कम करने, ऊर्जा दक्षता में सुधार करने और टिकाऊ समुद्री प्रथाओं को अपनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

Q9. QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2027 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. भारत QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2027 में विश्व स्तर पर 13वें स्थान पर रहा।
2. भारत दक्षिण एशिया में प्रथम स्थान पर रहा और शीर्ष 15 में शामिल एकमात्र दक्षिण एशियाई देश था।
3. संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) ने सूचकांक में शीर्ष स्थान बरकरार रखा।
4. भारत ने फ्यूचर ऑफ वर्क संकेतक में 5वीं रैंक हासिल की।

- (a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1, 3 और 4
(d) 1, 2, 3 और 4

Ans.(d)

Sol. उत्तर

- (d) 1, 2, 3 और 4

व्याख्या

- कथन 1 सही है क्योंकि भारत 89.4 के समग्र स्कोर के साथ विश्व स्तर पर 13वें स्थान पर रहा।
- कथन 2 सही है क्योंकि भारत दक्षिण एशिया में प्रथम स्थान पर रहा और शीर्ष 15 में शामिल एकमात्र दक्षिण एशियाई देश था।
- कथन 3 सही है क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने 99.2 के स्कोर के साथ पहला स्थान बरकरार रखा।
- कथन 4 सही है क्योंकि भारत फ्यूचर ऑफ वर्क संकेतक के तहत 5वें स्थान पर रहा।

Information Booster

- QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2027 को क्वाक्रेलेली साइमंड्स द्वारा जारी किया गया था।
- सूचकांक ने 89 देशों का मूल्यांकन किया, जिसमें निम्नलिखित संकेतकों का उपयोग किया गया:
- उच्च शिक्षा प्रदर्शन
- श्रम बाजार मेट्रिक्स
- कौशल-अंतर विश्लेषण
- AI परिवर्तन तत्परता
- तृतीय-पक्ष डेटासेट

शीर्ष 3 देश:

1. संयुक्त राज्य अमेरिका – 99.2
2. ऑस्ट्रेलिया – 97.5
3. यूनाइटेड किंगडम – 96.6

Additional Knowledge

संकेतकों में भारत का प्रदर्शन:

- कौशल संरेखण – 18वां
- शैक्षणिक तैयारी – 22वां
- फ्यूचर ऑफ वर्क – 5वां
- आर्थिक परिवर्तन – 14वां
- भारत सूचकांक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला निम्न-मध्यम-आय वाला देश बनकर उभरा।
- सूचकांक भविष्य की कार्यबल मांगों के लिए देशों की तैयारियों को मापता है, विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और तकनीकी परिवर्तन के युग में।

Q10. एकीकृत आपराधिक न्याय प्रणाली (ICJS) को मजबूत करने के लिए जून 2026 में केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा शुरू किए गए चार डिजिटल पुलिसिंग ऐप्स में से कौन सा नहीं है?

- (a) NCRB-अभिज्ञान
- (b) e-अभियोजन 2.0
- (c) e-फोरेंसिक 2.0
- (d) डिजी लॉकर जस्टिस

Ans.(d)

Sol. उत्तर: (d) डिजी लॉकर जस्टिस

व्याख्या

- केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जून 2026 में एकीकृत आपराधिक न्याय प्रणाली (ICJS) को मजबूत करने के लिए चार डिजिटल पुलिसिंग एप्लिकेशन लॉन्च किए।
- लॉन्च किए गए चार एप्लिकेशन थे:
- NCRB-अभिज्ञान
- आपराधिक प्रक्रिया पहचान (CrPI)
- e-अभियोजन 2.0
- e-फोरेंसिक 2.0
- इन अनुप्रयोगों का उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), बायोमेट्रिक पहचान, फोरेंसिक एकीकरण और डिजिटल अभियोजन प्रबंधन के माध्यम से जांच, अभियोजन और सजा में सुधार करना है।

Information Booster:

- एप्लिकेशन गृह मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा विकसित किए गए थे।
- इन्हें नई दिल्ली में आयोजित 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन के दौरान लॉन्च किया गया था।

• पहल का उद्देश्य प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) पंजीकरण से लेकर सजा तक तीन साल के भीतर न्याय प्रक्रिया को पूरा करना है।

• यह ICJS ढांचे के तहत पुलिस, फोरेंसिक और न्यायिक प्रणालियों को एकीकृत करता है।

Additional Knowledge:

• उसी कार्यक्रम के दौरान, अमित शाह ने NAFEX.in के साथ निम्नलिखित भी लॉन्च किए:

• DRISHTI (सूचना, समर्थन, प्रशिक्षण और मानव इंटरफ़ेस के लिए डिजिटल संसाधन)

• एंटरप्राइज़ संसाधन योजना (ERP)

• NAFED कल्याण

• ICJS को पुलिस, अदालतों, जेलों, अभियोजन और फोरेंसिक प्रयोगशालाओं के बीच निर्बाध डेटा साझाकरण की सुविधा के लिए डिज़ाइन किया गया है।

• AI-सक्षम बायोमेट्रिक पहचान और डिजिटल फोरेंसिक से आपराधिक न्याय वितरण की दक्षता और पारदर्शिता में सुधार की उम्मीद है।


Adda247
INDIA'S NO.1 GOVT JOB PREP APP



All Government **ONE DAY EXAMS!**

**BANK**

**RAILWAY**

**SSC**

**TEACHING**

**STATE
EXAMS**

**Expert Live
Classes**

**Comprehensive
Study Material**

**Mock Tests &
PYQs**

**Performance
Tracking**

**25,000+ PDF
Study Material**

25,000+
FREE PYP PDFs
OR ATTEMPT AS
**MOCK TESTS**

START PRACTICING NOW! →